



न्यायालय श्रीमान मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्रामियर  
=====

निगरानी याचिका क्र०

तन 2018

I/निगरानी/छतरपुर/श्र०४५/२०१८/०१२९०

मुन्ना उर्फ भरत लाल दुवे पिता राम मिलन दुवे

निबाती बकस्वाहा बाडे क्र० । तहसील व थाना बकस्वाहा

जिला छतरपुर मृ०५०

.... निगरानीकाठी

बनाम

जबाहर तिंडे पिता श्री लच्छी लोधी निबाती

बाडे क्र० ४ बकस्वाहा जिला छतरपुर मृ०५० .... प्रतिनिगरानीकाठी

निगरानी याचिका धारा अंतर्गत 50 भू.रा.त. 1959 मृ०५०

अधिस्थ न्यायालय अपर ग्राम्यकृत महादेव सागर तंभाग सागर अपील क्र० 551

वी- १२१/ २०१५-१६ में पारित आदेश दिनांक १८/१/२०१८ के बिल्द निगरानी

कर्ता निम्न लिखि याचिका प्रस्तुत करता है कि :-

1. यह कि अधिस्थ न्यायालय आदेश दिनांक सर्व अधिस्थ न्यायालय की आदेश प्रति प्राप्त होने से याचिका समयाबधि में प्रस्तुत की जा रही है। आदेश की की मूल प्रमाणित प्रति सेलग्न है।

-ः प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

2. यह कि प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रति निगरानी कर्ता छारा बिचारणीय न्यायालय तहसीलदार बकस्वाहा के तमक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम बकस्वाहा की भूमि खारा न० ६८४/१/क/१/१ एक्टा ०.२३८ ह० भूमि जो कि दमोह रोड पर कुथे के पास स्थित है। वह इसका भूमि स्वामी है। जिस पर जबरन निगरानी कर्ता छारा सक टीन सेट की गुमटी जमा ली है। मना करने पर बिबाद करता है। सर्व अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया बिचारणी न्यायालय तहसीलबकस्वाहा छारा निगरानी कर्ता को नोटिस जारी किया गया जिसका उत्तर निगरानी

टीन सेट की गुमटी जमा ली है। मना करने पर बिबाद करता है। सर्व अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया बिचारणी न्यायालय तहसीलबकस्वाहा छारा निगरानी कर्ता को नोटिस जारी किया गया जिसका उत्तर निगरानी

19/2/18

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1290

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/03/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया।</p> <p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील विलंब से प्रस्तुत की गई है, जो अवधि वाह्य है। आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारण कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जबकि अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण अनिवार्य होता है। आवेदक अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष भी विलंब के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके।</p> <p>दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">~~~~~ प्रशासकीय सदस्य</p> 	